

then, if they import something from outside and they express the hope of a settlement, what is there to stop them from expressing disappointment at the failure?

**Shri Lal Bahadur Shastri:** I think in so far as what has been accepted, is accepted, and forms part of the communique. What has not been accepted or what will happen in future, it is a hypothetical question.

**Shri Basappa (Tiptur):** Will the Government consider the advisability of having a larger or a bigger delegation consisting of more members so that they might have more contact. (Interruption).

**Mr. Speaker:** Order, order.

**Shri Basappa:**.. on an occasion like this when we have to contact more members from the South African countries? On such occasions, is it advisable to have a bigger delegation to explain the matters? (Interruptions).

**Some hon. Members:** No, no.

**Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):** It is being said in the Press and elsewhere also that the reference to China as an aggressor against India and South-east Asia was omitted because some of the African States were opposed to it. It is also being said that the reference to Kashmir dispute was inserted because Pakistan insisted on it. If this is so, what is the positive advantage gained by India so far as attending the Commonwealth conference is concerned?

**Shri Lal Bahadur Shastri:** So far as the reference to India and Pakistan is concerned, as I said, there was no substantive discussion on that at all in the Commonwealth conference. Regarding the reference made to certain countries by the hon. Member—he has not named them—they also did not raise that issue in so far as this particular question was concerned. Our Minister in his first speech did make a reference about the

Chinese aggression. He made a reference in his speech; this reference was not made at the time of the consideration of the draft communique. The hon. Member has slightly misunderstood the position. I said that the Minister, while making his first speech, made a reference, but there was no discussion at the time of the consideration of the draft communique on all matters which were discussed in the Commonwealth conference.

**Some hon. Members rose—**

**Mr. Speaker:** Today I cannot allow more questions. Because so many Members are anxious, if some other opportunity is sought for, I will consider it.

16.33 hrs.

MOTION RE: FOOD SITUATION—  
 contd.

**श्री स० मो० बनर्जी :** अध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश की प्रसेम्बली में यह सवाल थाया कि बाखिर इतना जबरदस्त भ्रष्ट संकट क्यों पैदा हुआ, तो सरकार ने यह जवाब दिया कि फसल पर पाला पड़ गया था। लेकिन जब चीजों के भाव का सवाल हमारे सामने आता है तो हम देखते हैं कि अंग्रेज खाद्य पदार्थों के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि देश में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। पाले के कारण भनाज का दाम ज्यादा हो सकता था, लेकिन माचिस पर तो पाला नहीं पड़ा, पर उसका दाम भी मात नए पैसे या छः नये पैसे से बढ़ कर छः दस या दस नए पैसे हो गया। क्या दामदा पर भी पाला पड़ गया कि उसका दाम बढ़ गया? मुझे लगता है कि पाला फसल पर नहीं, सरकार का ध्यान पर पाला पड़ गया है और यही कारण है कि इनकी आँखों के आगे सप्ता में डूबी हुई एक तस्वीर के सिवा कुछ नहीं है।

पाटिल साहब ने अपने भाषण में गुजरात राज्य की वर्षा की धीर उतका मजाक उड़ाये

[श्री स० मी० बनर्जी]

की कोशिश की। उन्होंने बम्बई बन्ध की चर्चा की और कहा कि शहरों के लोगों को बहका दिया गया है। उत्तर प्रदेश बन्ध की भी चर्चा हुई। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि क्या ये चीजें जनता के प्रसंतोष की भ्रामकता नहीं हैं? गुजरात में लोग गांधी जी के प्रावशों पर चलने वाले हैं और भाज भी नन्दा जी और बसावड़ा जी जैसे महारथी वहाँ हैं जिन्होंने वहाँ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और शायद वहीं खत्म भी करेंगे। वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है यह सरकार को सोचना चाहिए। प्रहमदाबाद शहर में जहाँ कांग्रेस और भाई० एन० टी० यू० सी० के कहे बगीर पत्ता भी नहीं हिसल सकता वहाँ श्री याजनिक के काने पर, कमेटी के काने पर हड़ताल हो जाती है।

16.35 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

सभापति महोदय, मजदूरों ने हड़ताल इसी लिए की कि उनको सस्ता गल्ला सहुलियत के साथ मिल जाया करे। लेकिन जब वह गल्ला मांगने धागे गए तो उनको गोली मिली। एक दिन की हड़ताल थी, लेकिन जब पांच मजदूरों का खून बँधा तो जैसा कि होता है, खून टपकता है तो जमता है। और यह खून भी जमा और हड़ताल पांच दिन की हो गयी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसका सामना गोली या लाठी से नहीं किया। देश के प्रधान मंत्री ने होरडर्स से कहा कि 15 दिन के बन्दर अपना जखीरा हमारे वाले कर दो। इसी तरह की बात कही थी मुरारजी भाई देसाई ने कि जो देश में बार या तीन हजार करोड़ का सोना छिपा है उसे एक महीने में हमको दे दो। लेकिन वह सोना बाहर नहीं आया, जमीन के नीचे चला गया और मुरारजी भाई मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। इसी तरह जो होरडर्स से अपना जखीरा निकालने को कहा गया है वे भी नहीं निकालेंगे। हम यह

नहीं समझते थे कि हमारे प्रधान मंत्री 15 दिन का समय देंगे। मैं आप को बता सकता हूँ श्रीरैया में, कालपी धादि में बैंकों के गोदामों में गेहूँ भरा है। उन पर बैंकों के ताले पड़े हैं। किताबों में लिखा है—इसकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास आती है—कि भाइल सीड भरा है लेकिन इन गोदामों में गेहूँ और चना भरा है। लिखा है कि गोदाम में तम्बाकू भरा है लेकिन सामने तम्बाकू है और पीछे गेहूँ है। लिखा है कि लोहा भरा है, लेकिन उसके पीछे गेहूँ और चावल भरा है। लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं होती कि एनफोर्समेंट वालों को या सेंट्रल इंटेलीजेंस वालों को इन तालों को तोड़ कर इसकी जांच करने को कहे।

भाज शास्त्री जी के काने मात्र से जखीरे-बाज अपना जखीरा छोड़ने नहीं। मेरी मुश्किल बून इन्दिरा जी लखनऊ गई थी। बावजूद इसके कि वहाँ भुखमरी थी, उन्होंने कहा कि विरोधी दल के लोग स्कारसिटी साइकोसिस फैला देते हैं जिसके कारण जिसको घाठ सेर की जरूरत होती है वह बीस सेर खरीद कर अपने पास रखता है। मेरी मुश्किल बून की नजरों में होरडर है भूखी नंगी जनता और वे होरडर नहीं हैं जिन्होंने गल्ला छिपा कर रखा हुआ है। मुझे भफसोस हुआ उनकी यह बात सुन कर। वह भी आखिर एक मां है और उनके भी बच्चे हैं। जब उत्तर प्रदेश में बच्चे भूख से सिसक रहे थे वह ऐसी बात कह रही थी। यह अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि ऐसी हालत में जनता पर क्या बीत रही होगी। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश में भुखमरी का ऐसा नंगा नाच कभी नहीं देखा। ऐसा मामूल होता था कि सन् 1943 का बंगाल का नजारा वहाँ उपस्थित होने वाला है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन कोई धादमी तो भूखी नहीं मरा।

भी स० नो० बनर्जी : यह मरघट के सरदार हैं। इन को खुशी है कि कोई मरा नहीं। 12 या 14 प्रादमी मरे। कहा जाता है कि उनका हाट फेल हो गया इसलिए मर गए। इस देश में हाट इतना हलका बना हुआ है कि वह फेल हो जाता है। लेकिन जो ये 12-14 प्रादमियों की मृत्यु हुई इस के बारे में उत्तर प्रदेश प्रसेम्बरी में कांग्रेस के सदस्यों ने भी कहा।

श्रम में धांपका ध्यान बंगाल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं सात घाट दिन पहले बहाँ था। सरसों का तेल मिलता नहीं। नमक एक रुपए सेर है। चावल फेयर प्राइस शाप पर मिल जाये तो अच्छा है, धीर वैसे धांप लें तो अच्छा चावल तीन रुपए किलो है। धगर मामूली चावल लेना चाहें तो दो रुपये किलो मिल सकता है धीर बात की जाती है कि जनता को सस्ती दर पर गल्ला मुलभ करने के लिए फेयर प्राइस शोप्स खोली जा रही हैं। इस सरकार का बर्ताव तो मुझे एक बिखारी के समान मालूम होता है जोकि किसी के घर के प्रागे तो भल्लाह के नाम से एक चूटकी घाटे की फरियाद करता है, दूसरे के घर के सामने फिर जा कर खड़ा हो जाता है धीर कहता है कि रहीम के नाम से मौना के नाम से मुझ थोड़ा घाटा दे दी धीर इस तरह से फकीर घाटा डुकट्टा कर के बाजार में जाकर बेचता है। यह सरकार भी कमी तो धमरीका के पास जाती है धीर फरियाद करती है कि हमें भगवान के नाम से कुछ घाटा दे दो, कुछ गेहूँ दे दो। फिर यह सरकार धास्ट्रलिया के पास जाती है धीर उन से कहती है कि राज के नाम से हमें घनाज दे दो, कम्पुनिस्ट कंट्री से कम्पनिज्म के नाम पर घनाज की मांग करती है धीर इस तरह से बिबेनों से भीष मांग कर उस घनाज को यह सरकार फेयर प्राइस शोप्स से बिकवाती है। मेरी

समझ में उस शहर के बिखारी धीर हमारी सरकार में कोई फर्क नहीं है।

फेयर प्राइस शोप्स का जहाँ तक सबाल है वे एक तो पर्याप्त हैं नहीं धीर सब जगह वे खुली भी नहीं हैं धीर किलने लोग वहाँ पर आते हैं यह भी हमें देखना है। यह कहा जाता कि देश में धन्न नहीं है, धन्न की कमी है लेकिन लोगों को इस पर बिश्वास नहीं होता है कि देश में सचमुच धन्न नहीं है या उसकी कमी है क्योंकि धगर किसी में एक रुपये का एक सेर गेहूँ खरीदने की हिम्मत हो तो उसे ब धांसानी मिल सकता है। सवा सेर का या रुपये का एक सेर दो छटों का गेहूँ धगर कोई खरीदना चाहे तो उस शक्त् के लिए गेहूँ की कोई कमी नहीं धीर उसे दस मन भी मिल सकता है। लेकिन धगर वह ढाई सेर की तरफ ललचा गया या वह डेढ़ सेर रुपये का चावल खरीदने की तरफ ललचा गया तो उसे वह नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, किसी को यह बिश्वास नहीं है कि देश में धन्न संकट धाया हुआ है। धगर बाकई में हम देखते कि संकट की परिस्थिति है तो मैं यकीन दिनाता हूँ कि किस तरह से चीनी धाक्रमण के रूप में जब देश पर खतरा धाया था धीर उस हमले का साधुना करने धीर संकट का मुकाबला करने के लिए सारा देश एक प्रादमी की तरह एक साथ उठ खड़ा हुआ था वैसे इस समय भी हो जाता।

धाज कहा जाता है कि जो लोग धान्दोन करते हैं वे राष्ट्रद्रोही हैं धीर उनकी हरकतें राष्ट्रद्रोहिता की हैं . . . . .

Mr. Chairman: The hon. Member should now conclude.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I was interrupted when I was speaking.

Mr. Chairman: That has been taken into account.

**Shri S. M. Banerjee:** I would take another three or four minutes.

**Mr. Chairman:** All right.

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार भले ही यह कहती रहे कि जो लोग एजिटेशन करते हैं वे राष्ट्रद्रोहिता का कार्य कर रहे हैं लेकिन मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर यह संकट इसी तरीके से बढ़ता गया और यही परिस्थिति हमारे देश में रही तो हमारी सरकार बम्बई बंद, महाराष्ट्र बंद से भले ही नाराज हो जाय या हमारे गृह मंत्री कहें कि भारत बंद होगा तो उस का मुकाबला किया जायगा। ठीक है मुकाबला प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण से उस का मुकाबला करने के लिए लेकिन यह मत भूल जाइये कि हमारे देश के लोग भी खड़े होंगे और अगर इसी तरीके से हासत रही तो भारत बंद होगा और इस सरकार को जबरदस्ती गद्दी से उतार कर धरती पर लाया जायगा। यह बिहकुल सही बात है। इसलिए आप के महज नाराज होने से यह मामला हल होने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि आज आप और हम सब बाहर प्रायें, इस्तीफे दें और इस महंगाई से मसले को लेकर दुबारा देश भर में चुनाव हो जायें। फूलपुर में भेजिये किसी को तब आप को पता चलेगा कि हालत क्या बन रही है। उत्तर प्रदेश में जाकर लोगों की हानत को देखिये तब आप को पता चलेगा कि आप हैं कहाँ। मैं चाहता हूँ कि आप बात के तकाजे को पहचानें और कम से कम कुछ फंसले लीजिये। वैसिलेशन मत कीजिये। करें या न करें इस के बीच में झटक कर मत रह जाइये। अगर आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर डालिये। अगर आप जमाखोरों और ब्लैक मार्केटर्स को सजा देना चाहते हैं तो उनको जरूर सजा दीजिये वरना इस तरीके से कि श्री मन्दा दिल्ली शहर में भेस बदल कर घूम लें, उससे यह समस्या हल होने वाली नहीं है। जखीरेबाज श्री भेस बदल कर घूमेंगे और दोनों एक दूसरे

को पहचानेंगे नहीं। इसलिए यह महज भेस बदलने का ही सवाल नहीं है। उदाहरण से अपनी इंसानों की तराजू को, डिफेंस आफ इंडिया क्लस को जिसके कि मातहत आपने हथारों इंसानों को बन्द कर रखा है। क्यों नहीं आप इस के मातहत उन मुनाफाखोरों, जमाखोरों और ब्लैकमार्केटर्स को सजा देते? देश में एक वातावरण पैदा कीजिये और उनके साथ सख्ती के साथ पेश भाइये करना देश की भाखादी खतरे में पड़ेगी। लिहाजा मेरा सुझाव यह है कि स्टेट ट्रेडिंग फुडगेंस में होनी चाहिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बैंक ऐडवांसज बन्द हों। स्पेकुलेशन और यह स्ट्रुबाजी को बन्द होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक प्राइस स्टैबिलाइजेशन बोर्ड जल्द से जल्द वजूद में प्राये। इसी सेशन में सरकार के प्रति भविष्यवास का प्रस्ताव धा रहा है, मैं दुबारा यह कहना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष में जो एक नज्जारा है वह आप सब लोगों के सामने है। वह एक सैम्पल है, एक नमूना है और समय रहते आप को चेत जाना चाहिए। बम्बई बंद, महाराष्ट्र बंद, उत्तर प्रदेश बंद, अगर इस नमूने से आप लोग चेत नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा भारत बंद होगा, भले ही लोगों की लाशें क्यों न सड़कों पर बिछ जायं, लेकिन भारत बंद होगा और लो इस सरकार को बदले और चैन नहीं लेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि This Government has miserably failed and is trying to harvest on the dead bodies of the people.

**Mr. Chairman:** Will the hon. Member please conclude his speech?

**Shri S. M. Banerjee:** I am only saying this. Let them realise the gravity of the situation. The line between hunger and anger has become thinner. Once that disappears, there is going to be a revolution which this Government will be unable to face.

Mr. Chairman: Shri Jaswant Raj Mehta....Is he not willing to speak?

Shri J. R. Mehta (Pali): I would like to speak tomorrow.

Mr. Chairman: Shri Sham Lal Saraf.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): Mr. Chairman, the motion before the House has been discussed for the whole day today and I have heard three speeches from the Opposition. These speeches were critical in general, but certainly there were some constructive suggestions also.

To my mind, the main question is of production. As far as production of foodgrains is concerned, particularly of cereals, it is mainly in the hands of the States. I have several times explained it in some detail while speaking in this House. At one time I handled these departments in my State and I can say that as far as production in the States is concerned, the Central Ministry has little hand in it; rather, I should say, there is no responsibility and they should take this today.

So, what is needed is to gear up the methods of production. If the States move in the right direction and if the Centre provides all the help that is necessary, I think, they will be in a position to give more and more production.

Apart from production, there is the question of distribution. As far as distribution is concerned, several views have been expressed in the House today. Some said that the zonal system of movement should be stopped; others say that it should be there. I personally feel that some sort of a restriction on movement is necessary and it should be there, where certain contiguous areas are concerned, there should be some relaxation.

Shri Lehri Singh pointed out a very important and cogent matter and that

is for the consideration of the Central Food Minister. In the Punjab in those areas that comprise East Punjab excepting Haryana Prant, wheat and rice are in abundance but unfortunately to the contiguous area of Haryana their movement is absolutely stopped. I think, in such matters there should be some freedom of movement of cereals. I hope, the hon. Food Minister will kindly give consideration to this suggestion that I am placing before him. Sometimes this stoppage of food movement has very adversely affected the food situation in certain States. It is not that I advocate that there should be absolutely free movement, but some such movement should be permitted, that would have a healthy effect on foodgrain prices in that part of the State, that is, that part of East Punjab.

Then, there is the distribution aspect. On distribution also, I would say that the Centre should take the States into confidence and formulate schemes as to how it should be collected, how it should be stored and how it should be distributed.

Thirdly, as far as imports are concerned, as one of our ex-Food Ministers this morning advocated a short-term scheme of importing food, I absolutely agree with him. But to always rely on food imports will be very difficult politically as well. About that also, we have to be very careful.

I would not, of course, take much time of the House but I would like to place before the hon. Minister a few practical suggestions. First of all, ever since I came to this House, I have been feeling that the Central Ministry of Food and Agriculture, particularly with regard to Food, are taking much of the responsibility upon themselves without making the States feel an equal responsibility in this behalf. That is to say, if I ask the

[Shri Shah Lal Saraf]

Food Minister as to whether he is well-informed about food production methods and measures adopted in a particular State, I am sure he will not be in a position to say exactly what is the position. That is because even now the proper methods have not been evolved and adopted in the various States. He should keep himself in absolute touch from month to month, even from day to day, with what is happening in the States as far as the food production part is concerned.

Then, with regard to making our agriculture more intensive, say, about the use of fertilisers, I must say that not only the fertilisers are sold at a very high price in our country but in a number of States they are not available. Therefore, proper measures have to be taken which will make available fertilisers to farmers at reasonable prices so that they use more and more fertilisers.

So far as taccavi and other loans are concerned, I may say, in areas where there is some sort of a political consciousness or there are people who agitate in certain respects in such areas, they may get these loans, otherwise loans are not freely available to farmers in a desirable way.

As far as taking over the wholesale trade is concerned, that is absolutely necessary. I am one with the Food Minister. That can be the only answer to hoarding wherever it is at the moment being resorted to. The population is rising year after year and the food habits are also changing. Both amongst the rural and urban populations, the food habits are changing. Personally, I feel that particularly with regard to such of the cereals, like, rice, many wheat-eating people have begun to take rice. For instance, I know about Punjabi friends who used to take very little of rice and who now take rice. There is

hardly a place or a house where they do not take rice.

Shri D. C. Sharma: You are perfectly right.

Shri Sham Lal Saraf: Therefore, my submission is this. A number of things have to be done. There is the educative aspect and then you have to give full attention to the production part of it. You must make things available at reasonable prices, like, fertilisers and other things. Then, also a concerted policy, a very well-thought-out policy is needed in which the Centre and the States must have a full share of responsibility. It is then alone, we will be able to go ahead.

Coming to the question of the utilisation of irrigation potential, I can give a number of instances where we have not fulfilled the targets. We have taken up a number of irrigation projects, large-sized, medium-sized as well as small-sized ones. But in a number of cases, the targets have not been fulfilled. We had laid down some targets in the First Plan, the Second Plan and the Third Plan in this respect, but I can make bold to say that in about 80 per cent of the cases, the targets have not been fulfilled, and when the targets have not been fulfilled, naturally, the expected results are also not there. Therefore, it is very important that the other Ministries concerned must give their full support and function in full co-ordination with the Central Ministry of Food and Agriculture. Only then shall we be in a position to assess the cumulative effect of all the efforts that we are putting forth in this direction. But what do we find? I can point out a number of instances in the north, south, east and west, where a number of big projects have been taken on hand, but where in most of the cases, I am rather pained to say that the targets have not been fulfilled, with the result that the achievements expected are also not there.

As my hon. friend Shri H. N. Mukerjee said this morning, we must not import politics in our food matters. We must tackle the food problem as a national problem, and everyone of us must contribute his mite to a solution of this problem, whether it be at the Central level or the State level. Then alone shall we be in a position to solve this burning problem of the day in respect of which I do not know for how long it would continue.

Then, I would refer to the question of floods also. Yesterday, I was coming from my place by air to Delhi, and I saw from the plane that most of the areas in Punjab were inundated. Punjab is almost the granary of the north. If this be the position there, I do not know what would happen tomorrow. While flying over the mountainous areas, I saw that at a number of places, the catchment areas of even some of the small rivers and streams had been absolutely denuded of trees. What have we done in that direction? Luckily, the Central Minister of Food and Agriculture is also in charge of afforestation and forests. A concerted drive at afforestation is also very necessary. We have talked about it, and we have had also funds allocated for this purpose, but I am sorry to say that we have not taken enough steps in that preventive direction. You can take any State, for example, in this connection, and you will find that a concerted drive has not been made in this direction in that State. I know that certain smaller schemes have been taken on hand, but I feel that no concerted effort has been made to minimise the damages caused by floods. Today, therefore, the result is that even some of the dry streams are in spate. For instance, the Ghaggar where generally you do not find even a drop of water has inundated several areas in Rajasthan.

Keeping all these in view, it would be seen that this is a problem which cannot be solved with any agitational approach. This cannot be solved by

injecting or importing politics into it or by importing factional elements into it. It can only be solved with a proper understanding of the problem at the Central and the State levels. Proper plans should be chalked out in which everybody must have his say, and the States also must be allocated their share of responsibility, and all concerned Ministries should lend their helping hand to the Central Ministry of Food and Agriculture; then alone we shall be in a position to solve this problem, of course, not today, but in the years to come.

With these few submissions, I would once again point out that imports are necessary now. I would like to say a word also about storage. This also has a psychological effect on the people. In spite of the fact that some areas are surplus, if we remove the surplus from those areas to other areas in order to feed those areas and leave only a lesser quantity in those surplus areas, it creates a psychological effect on the people there. That also has to be kept in view. Take, for instance, what happened in Punjab. The surplus foodgrains from Punjab were moved all at once at one time, and the result was that the prices shot up like anything there.

So, this is a very delicate problem, and it has to be handled very carefully. I am very happy that such an intelligent Minister as Shri C. Subramaniam has been put in charge of this department, and I hope that he will handle it very carefully, and I am sure he will have the support of everybody. I can assure him that the country is with him. If he continues this present drive and seeks support from others, I am absolutely sure that he will have that support, and he will be able to solve this problem that is so very acute today.

17.00 hrs.

Mr. Chairman: I will now call upon Dr. M. S. Aney. He might just begin and then continue tomorrow.

Dr. M. S. Aney: I am glad that you

[Dr. M. S. Aney]

have called upon me to begin my speech to be completed tomorrow.

In my opinion, the question before the House has not been properly placed by the Mover. He only made some preliminary remarks and said that the motion is for the consideration of the House. I think this was not fair to the House. We should know from the Mover of the Motion himself the real causes of the situation to be discussed here without leaving the matter vague.

My hon. friend, Shri Mahatab, who spoke on behalf of the Congress, said that the real question before the House is not a long-term problem to

be solved but a short-term one, namely, to meet the immediate situation. Others who spoke on behalf of the Congress have spoken in terms of a long-term solution of the food problem. We have to be clear in our minds as to what the bearings of the problem are. .

**Mr. Chairman:** The hon. Member may continue tomorrow.

17.01 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, September 8, 1964/Bhadra 17, 1886 (Saka).*